मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता । दुनियां के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है । दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 38 • अगस्त 1991 50 पैसे

ईस्ट इन्डिया कॉटन
मजदूरों की एक जीत

विभिन्न नामों से व शाखाओं में कपड़ा बुनने, प्रोसेसिंग व छपाई करने और सिलाई करने वाली ईस्ट इन्डिया कॉटन मिल्स फरीदाबाद की जानी-मानी कम्पनी है। फरीदाबाद में 1977-79 के मजदूर उभार के समय ईस्ट इन्डिया के मजदूर अगवा कतारों में थे। मजदूरों के इस उभार को कुचलने के लिए ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट ने वह गुन्डागर्दी की कि यह मैनेजमेन्ट फरीदाबाद-भर में कुख्यात हो गई। अक्टूबर 79 में पुलिस ने मजदूरों को गोलियों से भून कर फरीदाबाद के उस मजदूर उभार को दबाने में सफलता पाई थी। ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट उस खून-खराबे के बाद कुछ अधिक ही नंगा नाची है। दाल फराई नाम वाले अपने गुन्डा गिरोह के जरिए पिछले 12-13 साल से यह मैनेजमेन्ट विभिन्न प्रकार की मजदूर हलचलों को कुचलने में कामयाब हुई है। ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट ने 1983 में अपनी जूट मिल बन्द कर दी और वहाँ से निकाले 900 मजदूरों को अब तक उनका हिसाब तक नहीं दिया गया है। **ईस्ट इन्डिया की इस कुख्यात मैनेजमेंट के खिलाफ पावरलूम के कुछ मजदूरों ने एक जीत हासिल की है। इस मैनेजमेंट के हव्वे को कुछ हद तक इन मजदूरों ने दूर किया है और अपने साथी मजदूरों के लिए राह खोली है।**

हरियाणा में शासक पार्टी ने चुनावी चाल के तौर पर जून 89 से न्यूनतम वेतन के नये ग्रेडों की घोषणा की। इसके खिलाफ कई मैनेजमेन्टों ने हाई कोर्ट में केस कर दिया। ईस्ट इन्डिया मैनेजमेन्ट भी उनमें एक थी केस की आड़ में मैनेजमेन्ट द्वारा नये ग्रेड लागू नहीं करने के खिलाफ नवम्बर 89 में भी ईस्ट इन्डिया मजदूरों ने वेतन नहीं लेने जैसे सामुहिक कदम उठाये थे तथा इस पर इन मजदूरों की तनखा कुछ बढ़ा दी गई थी। **मई 90 में हाई कोर्ट में फैसला हुआ : हरियाणा सरकार और मैनेजमेन्टों के वकीलों ने नये ग्रेड जून 89 की जगह जनवरी 90 से लागू करने का समझौता किया था—न्यूनतम वेतन का केश लड़ने के लिए हाई कोर्ट में वकील खड़ा करने के नाम पर फरीदाबाद में भी यूनियनों ने मजदूरों से काफी पैसा बटोरा था पर उन्होंने इस केस में हाई कोर्ट में कोई वकील खड़ा नहीं किया। इस प्रकार हरियाणा में मजदूरों का करोड़ों रुपया मैनेजमेन्टों व शासक पार्टी के नेताओं की जेबों में और लाखों रुपए यूनियन नामधारी बिचौलियों की पाकेटों में गया।** खैर।

हाई कोर्ट में हुए समझौते के बाद ईस्ट इन्डिया के पावरलूम के कुछ मजदूरों ने पाया कि नये ग्रेड के अनुसार उनका जो न्यूनतम वेतन स्केल बनता है उसके अनुसार मैनेजमेन्ट उन्हें तनखा नहीं दे रही। डरते-झिझकते हुये इस प्रकार के लगभग 100 मजदूर अलग-अलग व समूहों में मैनेजमेन्ट अधिकारियों व यूनियन लीडरों से मिले पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर अक्टूबर 90 में इन 100 मजदूरों ने लिख कर मैनेजमेंट से मांग की कि उन्हें वेतन में जो 65 रुपये कम दिए जा रहे है उनका भुगतान किया जाए। मैनेजमेन्ट ने कोई जवाब नहीं दिया महीने-भर बाद यूनियन लीडरों ने इन मजदूरों को कहा कि उनका जो बनता है उसी हिसाब से उन्हें वेतन दिया जा रहा है।

12-13 साल की खुली गुन्डागर्दी के मद्देनजर पावरलूम के इन मजदूरों ने डरते-डरते दस्तखत करके मैनेजमेन्ट से मांग की थी। अब इन मजदूरों ने दूसरा कदम उठाया। नवम्बर 90 में इस सम्बन्ध में इन 100 मजदूरों ने डी एल सी को आवेदन दिया। ईस्ट इन्डिया मैनेजमेन्ट हरकत में आई। इन मजदूरों के एडवांस और कोआपरेटिव स्टोर से राशन पर मैनेजमेन्ट ने रोक लगा दी। धमकियों का सिलसिला भी चला पर यह मजदूर झुके नहीं। **डी एल सी द्वारा बुलाई कई मीटिंगों में तो मैनेजमेन्ट उपस्थित ही नहीं हुई और जब उपस्थित हुई तब उनके प्रतिनिधि ने साफ-साफ कह दिया कि सरकारी ग्रेड के हिसाब से उन मजदूरों को 65 रुपये प्रतिमाह और दिए जाने चाहिए पर मैनेजमेन्ट नहीं देगी क्योंकि सवाल उन 100 मजदूरों का ही नहीं था बल्कि पाँच हजार मजदूरों को कन्ट्रोल करने का था। मजदूर स्वयं कदम उठायें और अपनी मांगें हासिल करे यह मैनेजमेन्ट को मंजूर नहीं था। ईस्ट इन्डिया मैनेजमेन्ट के प्रतिनिधि ने बीसियों मजदूरों के सामने खुल कर कहा कि मैनेजमेन्ट सुप्रीम कोर्ट तक जायेगी पर उन्हें पैसे नहीं देगी।** डी एल सी और लेबर इन्सपैक्टर की जिम्मेदारी थी कि वे ईस्ट इन्डिया मैनेजमेन्ट के खिलाफ न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम के तहत कार्रवाही करें पर उन्होंने ऐसी कार्रवाही नहीं की। अनसुना कर रही, मना कर रही मैनेजमेन्ट को डी एल सी रिक्वेस्ट करता रहा और कागज लेबर इन्सपैक्टर को बढ़ाता रहा।

इन हालात में इन 100 मजदूरों ने दिसम्बर 90 में पेमेन्ट ऑफ वेजेज अधिकारी के सम्मुख जनवरी 90 से बकाया वेतन के लिए केस दायर किया। **इन मजदूरों ने किसी को अथोरिटी लेटर नहीं दिया, कोई वकील नहीं किया, किसी यूनियन लीडर को आगे नहीं किया। शिफ्टों के हिसाब से 20—30 मजदूर केस की हर तारीख पर उपस्थित हुए।** और यह सब इन मजदूरों ने पेमेंट आफ वेजेज अधिकारी तथा लेबर डिपार्टमेंट के अन्य अफसरों व कर्मचारियों की सलाह के खिलाफ किया। यह कदम इन मजदूरों ने वकीलों व कई अन्य सलाहकारों की सलाह के खिलाफ उठाया। **बिचौलियों द्वारा पहुँचाई चोटों से कुछ सबक ले कर इन मजदूरों ने कानूनी पचड़ों व अन्य झन्झटों को स्वय झेलने के लिए यह कदम उठाये।**

फरवरी 91 में यह मजदूर डी सी से भी मिले पर डी एल सी को रेफर के सिवा और कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैनेजमेन्ट ने इन मजदूरों को भड़काने के लिए उकसावेबाजों को भी आजमाया पर यह मजदूर चक्कर में नहीं आये। डी एल सी — लेबर इन्सपैक्टर द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत ईस्ट इन्डिया मैनेजमेन्ट के खिलाफ केस नहीं करने पर इन मजदूरों ने स्वयं इस प्रकार का केस भी मई 91 में दायर किया।

ईस्ट इन्डिया के पावरलूम के 100 मजदूरों द्वारा बकाया वेतन के लिए दिसम्बर 90 में दायर केस को पेमेंट ऑफ वेजेज अधिकारी ने खारिज करके, रिजेक्ट करके फैसला 24 जुलाई 91 को भेजा और 24 जुलाई 91 को ही ईस्ट इन्डिया मैनेजमेन्ट ने 65 रुपये महीना के हिसाब से 8 महीनों का बकाया वेतन इन मजदूरों को बांट दिया।

मैनेजमेन्ट, बिचौलिए, लेबर डिपार्टमेन्ट, प्रशासन, पूंजीवादी कानून आदि की हकीकत की एक झलक तो इस घटनाक्रम में दिखाई दी ही है, **मजदूरों द्वारा स्वयं पर भरोसा करके कदम उठाने के फायदों की एक झलक भी यहाँ नजर आई है।** इन मजदूरों ने ईस्ट इन्डिया मैनेजमेन्ट से बीस-तीस लाख रुपये झटक लिये हैं और पावरलूम के आटो के मजदूरों के लिए भी इतने रुपये मैनेजमेन्ट से वसूल करने की राह खोल दी है। सांप से ज्यादा खतरनाक सांप की दहशत होती है—पावरलूम के इन मजदूरों ने ईस्ट इन्डिया मैनेजमेन्ट हव्वे की कुछ हवा निकाल कर मजदूर आन्दोलन की राह से एक रोड़ा हटाया है।

—x—

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुचाने के प्रयास करना। 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना। 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लिये बेझिझक मिलें। टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

संपर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

कुछ बातें जिनका मतलब समझने की जरूरत है

1. केल्विनेटर मजदूरों को एस्कोर्ट्स मजदूरों के समर्थन की एच एम एस के फरीदाबाद में प्रमुख लीडर ने बढ़—चढ़ कर बातें की थी। 21 मई को केल्विनेटर मैनेजमेन्ट ने तालाबन्दी करके केल्विनेटर मजदूरों पर हमला बोला। एस्कोर्ट्स में कोई हलचल देखने में नहीं आई। केल्विनेटर में लॉकआउट को पचास दिन होने को आए तब बड़े-बड़े पोस्टर लगा कर कुछ संगठनों ने दस जुलाई को सांय पॉच बजे पहली आमसभा की। एस्कोर्टस के प्लांटों में साढ़े चार बजे छुट्टी होती है। बारह हजार से अधिक मजदूरों वाले एस्कोर्टस के किसी भी प्लॉट से दस जुलाई की मीटिंग में पचास मजदूरों का भी जलूस नहीं आया ....

केल्विनेटर मजदूरों की भागेदारी की वजह से बनी पॉच-सात हजार की उस मीटिंग में एच एम एस — बी एम एस—एटक—सीटू के लीडरों ने खूब भाषण झाड़े। यूनियन लीडरों ने कहा कि (ताला-बन्दी के पचास दिन बाद की पहली) आमसभा तो एकता दिखाने के लिए थी. संघर्ष का कार्यक्रम लीडर लोग दो-चार दिन बाद बैठ कर तय करेंगे ......

2 सपना-सौभाग टेक्सटाइल में एटक की अगुआई में 15 जुलाई से हड़ताल है। 31 जुलाई को एटक की यूनियनों की सपना-सौभाग के गेट पर मीटिंग रखी गई। बाटा में एटक की यूनियन है। बाटा में साढ़े चार बजे छुट्टी होती है। बाटा यूनियन ने दोपहर गेट मीटिंग में घोषणा की कि साढ़े पांच बजे बाटा फैक्ट्री से सपना-सौभाग के गेट पर जलूस जायेगा ....

3. ऑटोपिन मैनेजमेन्ट ने साल-भर से गुन्डागर्दी के लिये खुले छोड़ पहले लाल और फिर हरा झन्डाधारी यूनियन लीडर को जुलाई में कान पकड़ कर नौकरी से निकाल दिया। पिछले चार—पाँच साल में ही आंटोपिन मैनेजमेन्ट ने पीला—तिरंगा—लाल—हरा झन्डाधारी यूनियन लीडरों के रूप में कई लोगों को आंटोपिन मजदूरों के खिलाफ इस्तेमाल किया है और फिर उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है............

—x—

भिलाई

भिलाई स्टील प्लांट के इर्द-गिर्द के इन्डस्ट्रियल एरिया में मजदूरों का संघर्ष जारी है। 25 जून की सुबह छत्तीसगढ़ डिस्टीलरीज के निकाले हुए मजदूरों के जलूस पर पुलिस ने लाठियाँ और फिर गोलियां चलाई। 150 मजदूर घायल हुए, 107 मजदूर गिरफ्तार किये गये। इस हमले के खिलाफ 25 जून को ही दोपहर को दो हजार मजदूरों ने जलूस निकाला और एक सौ फैक्ट्रियों के मजदूरों ने सैकेन्ड शिफ्ट में हड़ताल की। मजदूरों के बल पर खड़े और भिलाई से अस्सी किलोमीटर दूर लोहा खदानों में स्थित शहीद अस्पताल के लोगों ने घायल मजदूरों की देखभाल की। जिन फैक्ट्रियों में 26 जून की छुट्टी नहीं थी उनमें उस दिन भी हड़ताल हुई। दल्ली राजहरा लोहा खदानों के मजदूरों ने पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज के खिलाफ जलूस निकाला। मुख्यत: यह मजदूरों द्वारा मजदूरों का सहयोग ही है जिसके बल पर अधिकतर कैजुअल व ठेकेदारों के मजदूरों का भिलाई में यह संघर्ष दस महीनों से जारी है और मैनेजमेन्ट-सरकार गिरोह से टक्कर ले रहा है।

-o-

थॉमसन प्रेस

थांमसन प्रेस काफी समय से संकट में है। पहले घोटाला और फिर लॉकआउट प्रकरण मरीज की हड़बड़ाहट के लक्षण थे। हर मर्ज की दवा का पूंजीवादी नुस्खा है : मजदूरों की बलि। लगातार यही नुस्खा इस्तेमाल करती आ रही थॉमसन मैनेजमेन्ट अब मजदूरों के शीश कलम करने की तैयारी कर रही है।

दो महीनों से पौने दो सौ परमानेन्ट मजदूरों को खोखला ट्रान्सफर कर खाली बैठाना+सौ के करीब परमानेन्ट मजदूरों को फरीदाबाद में खाली बैठाना+ठेकेदारों के वर्करों से काम करवाना+दो शिफ्ट में काम हो सकता है पर तीन शिफ्ट करके महीने में हफ्ते-भर मजदूरों को खाली बैठाना+ · सन्देश साफ है : थॉमसन मैनेजमेन्ट बड़े पैमाने पर छटनी की तैयारी कर रही है। मैनेजमेंट पहले धार पर लाटरी विभाग के वर्करों को रखती लगती है लेकिन नम्बर औरों का भी है अपनी रोजी पर मन्डरा रहे खतरे के खिलाफ थांमसन मजदूरों द्वारा कदम न उठाना बिल्ली को देख कबूतर द्वारा आंख मूंदने के समान है। इस सम्बन्ध में थॉमसन मजदूरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

-0-

मजबूत देश का मतलब

दिवालियेपन के कगार पर खड़े भारत को संकट से उबारने और उसे एक मजबूत देश बनाने के लिए नई नीतियों की आजकल खूब चर्चा हो रही है।

इस संविधान के दायरे में—नये संविधान की जरूरत—बुनियादी परिवर्तन के लिए खूनी क्रान्ति आदि आदि वाले इन्द्रधनुष की धुरी अथवा लक्ष्य भारत को एक मजबूत देश बनाना है। इसके वास्ते मजदूरों व अन्य मेहनतकशों से विभिन्न प्रकार की कुर्बानियां मॉगी जाती रही हैं, मांगी जा रही हैं। आइए मामले को थोड़ा कुरेद कर देखें।

पहली बात : यह कोई "भारतीय" विशेषता नहीं है। रूस-जर्मनी-इंग्लैंड-ब्राजील-मिश्र-ईरान-बर्मा.., दुनियाँ के हर हिस्से में करीब सौ साल से यह घटनाक्रम दोहराया जा रहा है। दूसरी बात अधिक महत्वपूर्ण है : भारत नाम की कोई समरस चीज नहीं है। भारत में भी एक बटा हुआ समाज है। यहां भी मजदूरों और पूंजी के नुमाइन्दों के हित एक दूसरे के विपरीत हैं। भारत के हित का मतलब यहां के पूंजीवादी हित हैं।

इतिहास में राष्ट्र देश रूपी राजनीतिक इकाइयाँ मन्डी के लिये उत्पादन के माफिक उभरी, जहां स्वयं मनुष्य की श्रम-शक्ति बिक्री के लिए एक वस्तु बन जाती है, उस पूंजीवादी उत्पादन द्वारा राष्ट्र—देश स्थापित हुए। और लगभग सौ साल से यह पूंजीवादी व्यवस्था मरणासन्न—पतनशील अवस्था में पहुच गई है। इस दौरान के पूंजीवादी व्यवस्था के संकट अपने को राष्ट्रों—देशों के संकटों के तौर पर भी अभिव्यक्त कर रहे हैं।

इसलिए देश को संकट से उबारने, देश की एकता-अखंडता की रक्षा करने, देश का विकास करने, देश को मजबूत करने आदि-आदि का मतलब आज पूंजीवाद के चरमरा रहे राजनीतिक खोल की मरम्मत करना है।

प्रोडक्सन की हमारी शक्तियां आज इतनी विकसित हो गई हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए हंसी-खुशी भरा खुशहाल जीवन सम्भव हो गया है। लेकिन प्रोडक्शन की इन शक्तियों का मानव हित में इस्तेमाल विश्व आधार पर ही किया जा सकता है। इसलिए देशों को तोड़ कर विश्व साम्यवादी समाज का निर्माण अब इन्सानों की जरूरत बन गया है।

-o-

केल्विनेटर

मैनेजमेन्ट के तालाबन्दी वाले हथियार का मजदूर जवाब नहीं दे पाये इसलिए 18 जुलाई को मैनेजमेंट की शर्त पर अपने सवा सौ साथियों को बाहर छोड़ कर मजदूरों को ड्यूटी पर जाना पड़ा।

अन्धी गली में फंस जाने पर बाहर निकलने के लिए केल्विनेटर मजदूर झुके पर टूटे नहीं। इसका शानदार सबूत मजदूरों ने पुलिस की गुन्डागर्दी के खिलाफ टूल डाउन करके दिया है।

दो महीने की तालाबन्दी और उसके बाद की घटनायें साफ-साफ दिखा रही हैं कि मैनेजमेन्ट व सरकार एक तरफ हैं तो मजदूर दूसरी तरफ हैं—मैनेजमेन्ट में अथवा सरकार में अपने पक्षधर ढूंढना मजदूरों के लिए दल-दल में धंसने की राह है। संघर्ष के तौर-तरीकों पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। मैनेजमेन्ट-सरकार गिरोहबन्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए केल्विनेटर मजदूरों की एकता तो जरूरी हैं ही, केल्विनेटर मजदूरों और फरीदाबाद की अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों का आपस में मिल कर कदम उठाना भी जरूरी है।

हां फरीदाबाद के ही आठ-दस साल के ऊषा-स्पिनिंग-भारतीय इलैक्ट्रिक स्टील-ईस्ट इन्डिया-हैदराबाद एस्बैस्टोज आदि-आदि के अनुभव से सबक ले कर केल्विनेटर मजदूरों को दो-चार लोगों द्वारा इधर-उधर मार-पीट वाले कदमों से बचना चाहिए। इस प्रकार के कदम मैनेजमेन्ट-सरकार गिरोहबन्दी को बहाने देते हैं। पुलिस रूपी संगठित गुन्डों तथा फुटकर गुन्डों को नंगा नाचने के लिए बहाने-भर की ही जरूरत होती है। मजदूरों की राह एकता, आँखों वाली एकता और हमलों के खिलाफ सामुहिक कदमों वाली राह है।

केल्विनेटर में हालत लम्बी खीच-तान के बन गये लगते हैं। हमारे विचार से ऐसे में आर-पार की लड़ाई वाले कदमों की बजाय गले में फंसी हड्डी, जिसे न उगल सकें न निगल सकें, वाले कदम उपयोगी होंगे। मजदूरों द्वारा एक के बाद दूसरी डिमांड पर मैनेजमेंट को झटके देना जहाँ मजदूरों की एकता को मजबूत करेगा वहीं मैनेजमेन्ट से लगातार कुछ झटकने में भी केल्विनेटर मजदूर सफल होंगे। विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

—o—

★ मार्क्सवाद शीर्षक लेखमाला की किस्त अगले अंक में। यहाँ नहीं दे पाने का हमें खेद है।

स्वत्वाधिकारी व सम्पादक शेरसिंह द्वारा आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद से प्रकाशित व अलकनन्दा प्रिंटिंग प्रेस C-III/206, सं. गां. मेमो. न. से मुद्रित